RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 101
दि. 09.08.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

पीएम मोदी के स्वागत के लिए चीन तैयार, ट्रंप से तनाव के बीच होगा दोस्ती का 'महा सम्मेलन'

(जीएनएस)।

चीन में होने वाली SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित भागीदारी का शी जिनपिंग ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। यह सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की।

'दोस्ती का सम्मेलन'

जियाकुन ने कहा, "चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का SCO तियानजिन समिट में भागीदारी के लिए स्वागत करता है। हमें विश्वास है कि सभी पक्षों के साझा प्रयासों से यह सम्मेलन एकजुटता, मित्रता और सार्थक परिणामों का प्रतीक बनेगा।" उन्होंने आगे कहा कि यह बैठक एससीओ को "एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी, जिसमें अधिक समन्वय, ऊर्जा और उत्पादकता देखने को मिलेगी।" चीन ने इस सम्मेलन को 'दोस्ती का सम्मेलन' बताया है।

यह संभावित यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसकी चीन पहले ही कड़ी आलोचना कर चुका है। पीएम मोदी चीन यात्रा से पहले जापान भी जा सकते हैं, जहां वे जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ इस सालाना द्विपक्षीय सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं।

पहले भी दो बार मोदी जा चुके हैं चीन

प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा का एक इतिहास रहा है। इससे पहले वे 2018 में दो बार चीन का दौरा कर चुके हैं। पहली बार अप्रैल में उन्होंने वुहान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अनौपचारिक शिखर वार्ता की थी। दूसरी बार, जून में किंगदाओ में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे।

2019 में भारत आए थे जिनपिंग

इसके बाद 2019 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे, जहां दूसरी अनौपचारिक शिखर बैठक हुई थी। यह बैठक 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश थी।

गलवान घाटी झड़प के बाद बदले थे समीकरण

हालांकि, 2020 में भारत-चीन संबंधों में भारी गिरावट आई, जब लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर झड़पें हुईं और गलवान घाटी में खूनी संघर्ष हुआ। जून 2020 की उस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली विस ने स्कूल फीस विनियमन विधेयक को मंजूरी दी, जिससे अभिभावकों को फीस वृद्धि पर वीटो पावर मिल गई

दिल्ली विधानसभा ने स्कूल फीस विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी दे

दी है, जिससे माता-पिता को फीस वृद्धि पर वीटो शक्ति मिल गई है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि स्कूल प्रबंधन एकतरफा फीस नहीं बढ़ा सकता। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अगर एक भी माता-पिता असहमत होते हैं, तो फीस वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के दक्षिण जोन के लांभा वार्ड में अर्बन फॉरेस्ट पार्क का लोकार्पण किया

मुख्यमंत्री ने अर्बन फॉरेस्ट पार्क में लगाई गई भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा का अनावरण किया

गांधीनगर, 08 अगस्त : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अहमदाबाद के दक्षिण जोन के लांभा वार्ड में मंच सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर विकसित किए गए अर्बन फॉरेस्ट पार्क का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया।

लांभा वार्ड में तैयार किया गया यह अर्बन फॉरेस्ट 4464 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इस गार्डन को 55 लाख रुपए की लागत से विकसित किया गया है।

इस अर्बन फॉरेस्ट में मियावाकी पद्धति से साग, खेर, बांस, सीसम और अर्जुन जैसे लगभग 8000 देशी पेड़ लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, यहां 250 मीटर लंबाई का वॉक-वे भी तैयार किया गया है।

अर्बन फॉरेस्ट पार्क के लोकार्पण अवसर पर अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, मनपा आयुक्त श्री बंछानिधी पाणि, शहर के विधायक, पार्षद और महानगर पालिका के पदाधिकारी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में अहमदाबाद महानगर पालिका ने अहमदाबाद शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के संकल्प को पूरा किया है।

अब, क्लीन सिटी अहमदाबाद को ग्रीन सिटी बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए महानगर पालिका ने मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश में 40 लाख पेड़ लगाने के लिए मिशन फॉर मिलियन ट्रीज 2025 अभियान शुरू किया है।

मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। बधाई सन्देश में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि रक्षाबंधन भाई-बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह व विश्वास का त्योहार है।

यह पर्व कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता व सद्भाव की भावना का प्रतीक है। रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व तो है ही, यह भारत की गुरु-शिष्य परम्परा का त्योहार भी है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण मास में आश्रम परम्परा में अध्ययन और यज्ञ आदि कर्म के उपरान्त यजमानों और शिष्यों को रक्षासूत्र बांधने की प्रथा थी, जिसका पालन रक्षाबंधन के रूप में भी किया जाता है।

बिहार चुनाव से पहले नक्सली साजिश का पर्दाफाश, सुरंग से एके-47 के 139 कारतूस बरामद, मचा हड़कंप

(जीएनएस)।

बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच नक्सल गतिविधियों की आहट ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के लंगुराही पहाड़ इलाके में सुरंग से अड-47 के 139 जिंदा कारतूस बरामद होने से सनसनी फैल गई है। उपद्रक और औरंगाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने 6 अगस्त को चलाए गए एंटी-नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान इस भारी मात्रा में गोलियां बरामद कीं। सुरंग में HHDMD डिवाइस से तेज सिग्नल मिलने पर जांच की गई और यह खतरनाक जखीरा सामने आया।

इस बरामदगी के बाद यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में आगामी चुनाव से पहले नक्सली नेटवर्क फिर से सक्रिय हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में मदनपुर थाना में FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है।

कैसे हुआ बरामदगी का खुलासा?

औरंगाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि, 6 अगस्त 2025 को औरंगाबाद पुलिस एवं एसटीएफ की टीम ने लंगुराही पहाड़ी क्षेत्र में कुछ संदिग्ध प्वाइंट चिन्हित कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आधुनिक उपकरण ललउ्टऊके जरिए सुरंगों में तलाशी ली गई। तेज सिग्नल मिलने पर एक सुरंग की जांच की गई, जहां से अड-47 के 139 जिंदा कारतूस बरामद हुए। बरामद कारतूसों के बाद मदनपुर थाना में कांड संख्या 328/25 दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, नक्सलियों की साजिश को नाकाम करने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। इस अभियान से नक्सलियों का मनोबल गिरा है और चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। औरंगाबाद पुलिस ने साफ किया कि नक्सल गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए छापेमारी और तलाशी अभियान तेज कर दिए गए हैं।

ट्रंप के 50% टैरिफ पर शशि थरूर ने अमेरिका को दी चेतावनी, बोले- क्या भारत की परवाह है?

(जीएनएस)।

अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाने का एक बड़ा फैसला किया है, जिसने दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में नई तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। इस कदम के बाद राजनीतिक और आर्थिक गलियारों में चचाओं का दौर शुरू हो गया है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस निर्णय को "चिंताजनक" बताते हुए अमेरिकी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं कि क्या वे भारत के साथ अपने महत्वपूर्ण रिश्तों की कद्र करते हैं या नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंधों को महत्व नहीं देता, तो भारत को भी उसी आधार पर अपने कदम उठाने चाहिए।

थरूर ने सुझाव दिया है कि भारत को अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर वर्तमान में लगाए जा रहे औसत 17% टैरिफ को बढ़ाकर 50% तक कर देना चाहिए। इससे व्यापार में संतुलन कायम हो सकेगा और भारत की राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का संरक्षण किया जा सके। इस पूरे विवाद शशि थरूर ने क्या कहा विस्तार से जानिए...

थरूर के अनुसार, अमेरिका और भारत के बीच करीबी रिश्ते और रणनीतिक साझेदारी रही है, लेकिन अगर अमेरिका ने अपना रवैया बदल लिया है, तो भारत को भी अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा, "अगर आने वाले दो से तीन हफ्तों में बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलता है तो ठीक है, लेकिन हमें अपने हितों की सुरक्षा करनी ही होगी।"

थरूर ने सुझाव दिया कि भारत को भी अमेरिका से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय भारत औसतन 17% टैरिफ लगाता है, लेकिन अब इसे अमेरिका के स्तर तक ले जाना चाहिए। "जब वे 50% कर रहे हैं तो हम 17% पर क्यों रुकें? हमें भी 50% करना चाहिए।"

दरअसल, बुधवार, 6 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत से आने वाले सामान पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया गया। इससे कुल शुल्क दर 50% हो गई।

ट्रंप ने इस कदम के पीछे भारत के रूस के साथ व्यापार, खासकर तेल खरीद को मुख्य कारण बताया। अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे "अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंगत" करार दिया और कहा कि देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

थरूर ने चेतावनी दी कि 50% टैरिफ का असर दोनों देशों के व्यापार पर पड़ेगा। वर्तमान में भारत का अमेरिका के साथ करीब 90 अरब डॉलर का व्यापार है। उन्होंने कहा कि "अगर हर चीज 50% महंगी हो जाएगी तो खरीदार भी सोचेंगे कि भारतीय सामान क्यों खरीदें?" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी देश को भारत को इस तरह से धमकाने का अधिकार नहीं है।

थरूर ने कहा कि आने वाले दो से तीन हफ्तों में भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है, जिससे कोई समाधान निकल सके। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि "अगर उस देश का रवैया बदल गया है, तो भारत को भी कई चीजों पर विचार करना होगा और अपने हित खुद देखने होंगे।

पीके की तीसरी किस्त ने उड़ाई एनडीए की नींद, सबूतों के साथ भाजपा के नेता-मंत्री को कटघरे में किया खड़ा

सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (पीके) ने एक बार फिर बिहार सरकार के बड़े मंत्री पर बड़ा हमला बोला है। पटना में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के तीसरे भाग में पीके ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

प्रशांत किशोर ने दावा किया कि दिलीप जायसवाल से रिश्वत लेकर फ्लैट खरीदने, एमजीएम मेडिकल कॉलेज को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने, और एम्बुलेंस खरीद में घोटाला हुआ है। पीके ने दस्तावेजी सबूतों के साथ भाजपा और इसके मंत्रियों को कठघरे में खड़ा किया।

भारत सरकार ने अमेरिका से हथियारों की खरीद बंद कर दी? रॉयटर्स के दावे पर रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा

(जीएनएस)।

भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ विवाद के बीच हथियार और विमान खरीद को लेकर नई हलचल मच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया था कि, भारत ने अमेरिका से रक्षा खरीद की अपनी योजना को रोक दिया है।

यह खबर ऐसे समय आई है, जब दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर तनाव लगातार बढ़ रहा है हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।

रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा?

मंत्रालय का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा खरीद संबंधी वार्ता में कोई रुकावट नहीं आई है और विभिन्न परियोजनाएं तय प्रक्रिया के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं। मंत्रालय ने रॉयटर्स की रिपोर्ट को 'झूठा और मनगढ़ंत' बताते हुए साफ किया कि टैरिफ विवाद का रक्षा खरीद पर कोई असर नहीं पड़ा है।

रॉयटर्स ने क्या कहा था?

रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत में असंतोष बढ़ा है। इस असंतोष के चलते केंद्र सरकार ने अमेरिका से नए हथियार और विमान खरीदने की योजना को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।

खबर में कहा गया कि इस फैसले की जानकारी तीन भारतीय अधिकारियों ने दी, जो मामले से सीधे तौर पर जुड़े हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर नाराजगी जताई थी और भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था। इससे पहले ही लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ को मिलाकर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया, जो किसी भी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार के लिए सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप लगाया था।

सोशल मीडिया पर दोस्ती..फिर इमोशनल ब्लैकमेल, मुंबई में 80 साल के बुजुर्ग से ठगों ने उड़ाए 9 करोड़

मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 80 वर्षीय बुजुर्ग को सोशल मीडिया के जरिये एक हाई-प्रोफाइल ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया गया। वे अब तक

भारत में मांसाहारी दुग्ध उत्पाद और चारा बेचना चाहता है अमेरिका, दूध के बाजार को अमेरिका हड़पना चाहता है। जबकि वेंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वुछ माह पहले ही दस हजार नई वृषि सहकारी समितियों को हरी झंडी दिखाई है। अगले पांच साल में इनकी संख्या दो लाख तक पहुंचाने की है। इन्हीं सहकारी संस्थाओं के जरिए वृषि और दुग्ध उत्पादों को भारत से लेकर एशिया और यूरोप तक बाजार में पहुंचाने की है।

तेजस्वी यादव को 16 अगस्त तक जमा करना होगा अपना ईपीआईसी, चुनाव आयोग ने क्यों दिया अल्टीमेटम?

(जीएनएस)।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी घमासान अपने चरम पर है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। पटना के निर्वाचन अधिकारी ने तेजस्वी को नोटिस भेजकर 16 अगस्त 2025 तक अपना वोटर आईडी जमा करने का अल्टीमेटम दिया है।

नोटिस में दावा किया गया है कि तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस EPIC नंबर को दिखाया, वह फर्जी हो सकता है। यह मामला बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया और वोटर लिस्ट विवाद के बीच और गमार्ता जा रहा है। आइए, जानते हैं इस सियासी ड्रामे की पूरी कहानी...

क्या है विवाद?

तेजस्वी यादव ने 2 अगस्त 2025 को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज दावा किया था कि उनका नाम बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से

हटा दिया गया है। उन्होंने EPIC नंबर RAB2916120 दिखाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इसे सर्च करने पर 'No Records Found' का मैसेज आया। तेजस्वी ने इसे सियासी साजिश करार देते हुए आरोप लगाया कि उनके जैसे बड़े नेता का नाम अगर वोटर लिस्ट से हट सकता है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा?

हालांकि, चुनाव आयोग ने तुरंत पलटवार करते हुए तेजस्वी के दावे को खारिज कर दिया। आयोग ने वोटर लिस्ट का वह पेज सार्वजनिक किया, जिसमें तेजस्वी का नाम EPIC नंबर RAB0456228 के साथ दीघा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 204 (बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पुस्तकालय भवन) में क्रमांक 416 पर दर्ज है। आयोग ने साफ किया कि तेजस्वी का नाम लिस्ट में मौजूद है और उनका दूसरा EPIC नंबर रिकॉर्ड में नहीं मिला।

सम्पादकीय

यूएस की लगातार कोशिश कि भारत दबाव में आकर उसके दुग्ध उत्पादों के लिए अपना बाजार खोल दे

भारत में मांसाहारी दुग्ध उत्पाद और चारा बेचना चाहता है अमेरिका दूध के बाजार को अमेरिका हड़पना चाहता है। जबकि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छह माह पहले ही दस हजार नई दुग्ध सहकारी समितियों को हरी झंडी दिखाई है। अगले पांच साल में इनकी संख्या दो लाख तक पहुंचाने की है। इन्हीं सहकारी संस्थाओं के जरिए वृषि और दुग्ध उत्पादों को भारत से लेकर एशिया और यूरोप तक बाजार में पहुंचाने की है। भारत में मांसाहारी दुग्ध उत्पाद और चारा बेचना चाहता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऊल-जलूल टैरिफ संबंधी घोषणाएं करके भारत पर बेवजह दबाव बनाने में लगे हैं। उन्होंने 1 अगस्त से भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एकतरफा निर्णय ले लिया है। यही नहीं ट्रंप ने रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त जुर्माना लगाने की बात भी कही है। यह टैरिफ देशी भारतीय दुग्ध एवं वृषि उत्पाद हड़पने की दृष्टि से भी लगाया गया है। जिससे भारत दबाव में आकर इन उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोल दे। लेकिन भारत भलि-भांति जानता है कि अमेरिका के सस्ते अनाज,पसु चारा और मांसाहारी चीज (पनीर) के लिए भारतीय बाजार खोल दिया जाता है तो किसान तो तबाह होगा ही शाकाहारी संस्कृति को भी पलीता लगेगा। साथ ही भारत सरकार जिन प्राथमिक वृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को बढ़ावा देकर वृषि और दूध उत्पादों को वैश्विक बाजार में लाने की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, वह विचार भी चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए सरकार ने साफ कह दिया है कि इन क्षेत्रों में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। वैसे भी अब यह सच्चाई सामने आ रही है कि एकतरफा वैश्वीकरण से दुनिया का भला होने वाला नहीं है। अतएव स्वदेशी उत्पादों के जरिए ही आत्मनिर्भर बने रहने की पहल जारी रखनी होगी। भारत इस दिशा में मजबूती से बढ़ भी रहा है। इसलिए ट्रंप जैसे वाचाल और सनकी शासक की परवाह करने की जरूरत नहीं है। भारत में गाय को माता यूं ही नहीं कहा जाता है। वे भारतीय ऋषि ही थे, जिन्होंने सबसे पहले जाना था कि गाय के दूध में ऐसे पोषक तत्व हैं, जो शरीर और दिमाग दोनों को ही स्वस्थ रखते हैं। यह दूध ही है, जिससे दही, मठा, मक्खन और घी जैसे सह-उत्पाद निकलते हैं। ये उत्पाद मिठाई की दुकानों से लेकर डेयरी उद्योग के जरिए करोड़ों लोगों के रोजगार का मजबूत मध्ययम बने हुए हैं। लंबे समय तक गाय से पैदा बैल पर ही भारतीय वृषि निर्भर रही है। इसी वृषि की जीडीपी में 24 प्रतिशत की भागीदारी है। भारतीय दुग्ध उत्पादन से लेकर दूध पीने में दुनिया में पहले स्थान पर है। इसी दूध पर अमेरिकी बाजार के कब्जे के लिए अमेरिका अपने यहां उत्पादित मांसाहारी दुग्ध उत्पाद और पशु चारा बेचना चाहता है। अन्य यूरोपीय देशों की निगाह भी इस दूध के व्यापार पर भी टिकी हैं। इस बाबत अमेरिका और भारत के बीच 500 बिलियन डॉलर के व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। इसी समझौते की सूची में अमेरिकन मांसाहारी दूध के उत्पाद शामिल हैं। भारत सरकार ने इस बाबत दो टूक कह दिया है कि अमेरिकी दुग्ध उत्पादों और पशु चारे को भारतीय बाजार का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। यह हमारे दुग्ध उत्पादक किसानों की आजीविका और उनकी संस्कृति की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा प्रश्न है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। दरअसल अमेरिका मांसयुक्त चीज (पनीर) और पनीर भारत में बेचने का इच्छुक है। इस चीज को बनाने की प्रक्रिया में बछड़े की आंत से बने एक पदार्थ का इस्तेमाल होता है। अत्यंत घिनौना वृत्य करके इसे चीज में मिलाया जाता है। शाकाहारी लोग इस प्रीया को देख भी नहीं सकते हैं। इसलिए भारत के शाकाहारियों के लिए यह पनीर वर्जित है। गौ-सेवक व गऊ को मां मानने वाला भारतीय समाज इसे स्वीकार नहीं करता। अमेरिका में गायों को मांसयुक्त चारा खिलाया जाता है, जिससे वे ज्यादा दूध दें। हमारे यहां गाय-भैंसें भले ही घूड़ेक चरे में मुंह मारती फिरती हों, लेकिन दुधारू पशुओं को मांस खिलाने की बात कोई सपने में भी नहीं सोच सकता ? लिहाजा अमेरिका को चीज बेचने की इजाजत नहीं मिल पा रही है। भारत में 13 जनवरी 1970 को फ्लड ऑपरेशन के साथ दूध का उत्पादन शुरू हुआ था। इसे ही श्वेत क्रांति का नाम दिया गया।

10 अगस्त, विश्व शेर दिवस : वन्यजीव संरक्षण में अग्रणी गुजरात

17 शेरों और 25 तेंदुओं की दहाड़ से गूंज रहा बरडा वन्यजीव अभयारण्य

गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी 891 हुई, शेरों के आवास के विस्तार और संरक्षण का सफल मॉडल बना बरडा अभयारण्य

बरडा जंगल सफारी बनी पर्यटकों के लिए नया आकर्षण, इको-टूरिज्म को मिला बढ़ावा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'प्रोजेक्ट लायनश और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के जरिए वन्यजीव संरक्षण में भारत की स्थिति हुई मजबूत

गांधीनगर, 08 अगस्त : भारत की शान एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास गुजरात में है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के अवसर पर गिर के अलावा बरडा वन्यजीव अभयारण्य में एशियाई शेरों की मजबूत उपस्थिति का उल्लेख प्रासंगिक होगा, जो वन्यजीवों, विशेषकर शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग ने बरडा अभयारण्य में वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग और सामुदायिक भागीदारी से शेरों के लिए अनुकूल आवास सुनिश्चित किया है। इसका सुखद परिणाम यह है कि बरडा अब 17 एशियाई शेरों का दूसरा घर बन गया है।

बरडा अभयारण्य में 17 एशियाई शेरों और 25 तेंदुओं की मौजूदगी

2023 की वन्यजीव गणना के अनुसार बरडा अभयारण्य में 17 एशियाई शेरों और 25 तेंदुओं की मौजूदगी है। वन एवं पर्यावरण विभाग ने घास के मैदानों की पुनर्स्थापना, शेरों के भोजन के लिए जानवरों की संख्या में वृद्धि तथा टेक्नोलॉजी-आधारित वन्यजीव ट्रैकिंग जैसे व्यापक संरक्षण उपाय किए हैं ताकि अभयारण्य अधिक से अधिक वन्यजीवों के लिए एक अनुकूल आवास बन सके। बरडा अभयारण्य की यह प्रगति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'प्रोजेक्ट लायनह्न के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें गिर के बाहर शेरों के आवास का विस्तार करना, वन्यजीवों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना शामिल है।

बरडा वन्यजीव अभयारण्य : वन्यजीव संरक्षण का एक रणनीतिक केंद्र

पोरबंदर के निकट स्थित बरडा वन्यजीव अभयारण्य आवास विविधीकरण के लिए 'प्रोजेक्ट लायनह्न के अंतर्गत एक मुख्य केंद्र है। बरडा वन्यजीव अभयारण्य अनिवार्य सुविधाओं और सुरक्षा के कारण शेरों के लिए एक आदर्श आवास बन गया है। यहां रेडियो कॉलर और रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसे उपकरणों के माध्यम से शेरों की निगरानी और अधिक प्रभावी बन गई है। बरडा वन्यजीव अभयारण्य में शेरों और तेंदुओं, दोनों की मौजूदगी एक स्वस्थ इकोसिस्टम को दशार्ती है।

पर्यटकों के बीच बरडा जंगल सफारी का आकर्षण, इको-टूरिज्म को बढ़ावा

गुजरात वन विभाग इको-टूरिज्म को प्रोत्साहन देने और संरक्षण को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 16 अक्टूबर से 15 जून के दौरान बरडा वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का आयोजन करता है। पर्यटकों को सफारी की एक ट्रिप (अधिकतम 6 लोग) के लिए कुल 2200 रुपए का खर्च करना होगा, जिसमें 1400 रुपए जिप्सी वाहन शुल्क, 400 रुपए गाइड शुल्क और सरकारी परमिट के लिए 400 रुपए का शुल्क शामिल हैं। इसके अलावा, पर्यटकों के लिए पार्किंग एरिया, वेटिंग लाउंज और सैनिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अभयारण्य में किलेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है, जो पूरे वर्ष पर्यटकों के लिए खुला रहता है।

वन्यजीव संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करके और लोगों को संरक्षण प्रयासों के केंद्र में रखकर वन्यजीव संरक्षण कर रहा है। स्थानीय समुदाय, विशेषकर मालधारी पशुपालक समूहों, इको-टूरिज्म और वन्यजीव संरक्षण में मदद करते हैं। यह सहभागी मॉडल केवल संरक्षण प्रयासों को ही मजबूत नहीं बनाता, बल्कि यह अभयारण्य की दीर्घकालिक सफलता में समुदायों की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है।

गुजरात में शेरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि

2025 में हुई शेरों की गणना के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी 891 तक पहुंच गई है, जिनमें से 50 फीसदी से अधिक शेर गिर संरक्षित क्षेत्र के बाहर निवास करते हैं। यह परिवर्तन 'प्रोजेक्ट लायनह्न के अंतर्गत आवास विस्तार और समुदाय-संचालित संरक्षण की प्रभावशीलता पर जोर देता है। बरडा का विकास बड़े मांसाहारी जानवरों के संरक्षण में भारत के नेतृत्व को दशार्ता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वैश्विक पहल- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) - शेर, बाघ, तेंदुआ और चीता जैसे मांसाहारी जानवरों के संरक्षण प्रयासों में भारत को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करती है।

एशियाई शेरों के संरक्षण में बरडा वन्यजीव अभयारण्य की उल्लेखनीय सफलता टिकाऊ विकास का एक शानदार उदाहरण है। यह मॉडल प्रधानमंत्री के विजन 'विकास भी, विरासत भीह्न के अनुरूप है, जो पर्यावरणीय विरासत के संरक्षण के साथ-साथ विकास भी सुनिश्चित करता है।

असम और त्रिपुरा के लिए विद्यमान केंद्रीय क्षेत्र विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) योजना के अंतर्गत 4,250 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ चार नए घटकों को अनुमति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम और त्रिपुरा के लिए विद्यमान केंद्रीय क्षेत्र विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) योजना के अंतर्गत 4,250 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ चार नए घटकों को अनुमति दी है।

विवरणः

- भारत सरकार और असम सरकार द्वारा असम के जनजातीय समूहों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओएस) के अनुसार असम के जनजाति बहुल गाँवों/क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये।
- भारत सरकार और असम सरकार द्वारा असम के दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनएलए)/दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल (डीपीएससी) समूहों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, असम के दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी/दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल के बसे हुए गाँवों/क्षेत्रों के उत्तरी कैचर हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये।
- भारत सरकार और असम सरकार द्वारा असम के उल्फा समूहों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, असम राज्य में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये।
- भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार द्वारा त्रिपुरा के नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) समूहों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, त्रिपुरा के जनजातियों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये।

वित्तीय पहलूः प्रस्तावित चार नए घटकों का कुल परिव्यय 7,250 करोड़ रुपये होगा, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपये असम (4000 करोड़ रुपये) और त्रिपुरा (250 करोड़ रुपये) के लिए विशेष विकास पैकेजों की विद्यमान केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएँगे, और शेष 3,000 करोड़ रुपये असम राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से प्रदान किए जाएँगे।

भारत सरकार, असम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों और संबंधित राज्य के जातीय समूहों के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, 4,250 करोड़ रुपये में से, वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए 4,000 करोड़ रुपये का परिव्यय असम के तीन घटकों के लिए और वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों की अवधि के लिए 250 करोड़ रुपये का परिव्यय त्रिपुरा के एक घटक के लिए है।

रोजगार सृजन क्षमता सहित प्रभावः

- बुनियादी ढाँचा और आजीविका परियोजनाएँ रोजगार सृजित करेंगी
- कौशल विकास, आय सृजन और स्थानीय उद्यमिता के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को लाभान्वित करेंगी
- स्थिरता लाने और प्रभावित समुदायों के मुख्यधारा में सम्मिलित होने की उम्मीद है

लाभः यह योजना विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों असम और त्रिपुरा के लिए लक्षित है। यह निम्नलिखित माध्यमों से भागीदारी को प्रोत्साहन देगीः

- विभिन्न मौजूदा सरकारी योजनाओं से पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं करने वाले कमजोर और वंचित लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार;

- युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन देना, स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, शिक्षा, कौशल और आय को प्रोत्साहन देना;

- देश के अन्य भागों से पर्यटकों की संख्या बढ़ाना, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अधिक अवसर सृजित होंगे। इसके माध्यम से, असम के जनजाति और दिमासा समुदायों, असम के विभिन्न अन्य ज़िलों में रहने वाले लोगों और त्रिपुरा के जनजाति समुदायों के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। यह विशेष विकास पैकेजों की चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत एक नई पहल है। पिछले समझौता ज्ञापन -आधारित पैकेजों (जैसे, बोडो और कार्बी समूहों के लिए) ने शांति स्थापना और विकास में सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित किए हैं।

पृष्ठभूमिः भारत सरकार, असम और त्रिपुरा राज्य सरकार और संबंधित जातीय समूहों (आदिवासी समूह - 2022, डीएनएलए/डीपीएससी - 2023, उल्फा - 2023, एनएलएफटी/एटीटीएफ - 2024) के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे और सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के माध्यम से शांति, समावेशी विकास और पुनर्वास को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

बहु-विषयक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (मेरिट) स्कीम के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों सहित 275 तकनीकी संस्थानों में 'तकनीकी शिक्षा में बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार' (मेरिट) स्कीम के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) के अनुरूप युक्तियों को क्रियान्वित कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना है।

यह एक 'केंद्रीय क्षेत्र स्कीम' है, जिसका कुल वित्तीय प्रभाव 2025-26 से 2029-30 की अवधि के लिए 4,200 करोड़ रुपये है। 4,200 करोड़ रुपये में से विश्व बैंक से ऋण के रूप में 2,100 करोड़ रुपये की बा' सहायता प्राप्त होगी।

लाभः

इस स्कीम के अंतर्गत अनुमानित 275 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों का चयन और सहायता की जाएगी। इनमें चुनिंदा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राज्य इंजीनियरिंग संस्थान, पॉलिटेक्निक और संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (एटीयू) शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, तकनीकी शिक्षा क्षेत्र से संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों को भी मेरिट योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम से लगभग 7.5 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।

रोजगार सृजन सहित प्रभावः

इस योजना से अपेक्षित प्रमुख परिणाम/आउटपुट इस प्रकार हैंः

भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटलीकरण कार्यनीतियां,

तकनीकी पाठ्यक्रमों के बीच बहु-विषयक प्रोग्राम के लिए दिशानिर्देशों का विकास,

छात्रों के अध्ययन और रोजगारपरक कौशल में वृद्धि,

छात्र समूहों में छात्रों की परिवर्तन दर में वृद्धि,

सुदृढ़ अनुसंधान और नवोन्मेषण वातावरण,

बेहतर गुणवत्ता आश्वासन और शासन तंत्र जिसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक लाभ होंगे,

प्रत्यायन में वृद्धि और बेहतर तकनीकी शिक्षा संस्थान-स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन,

प्रासंगिक, श्रम बाजार के अनुकूल पाठ्यक्रम और मिश्रित पाठ्यक्रम विकसित और लागू किए गए,

भावी शैक्षणिक प्रशासकों, विशेषकर महिला संकाय का विकास।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य

यह स्कीम सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों और पॉलिटेक्निकों में कार्यान्वित की जाएगी। ये युक्तियां एनईपी-2020 के अनुरूप हैं और इनका उद्देश्य भाग लेने वाले संस्थानों की गुणवत्ता, समानता और शासन को बढ़ाना है। इसे एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा और इसमें एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के माध्यम से केंद्र सरकार से भाग लेने वाली संस्थाओं को धन हस्तांतरण की सुविधा होगी।

आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान और एआईसीटीई, एनबीए आदि जैसे उच्च शिक्षा क्षेत्र में नियामकीय निकाय भी योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

रोजगार सृजनः

यह पहल एक व्यापक, बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से छात्रों की रोजगारपरकता में सुधार के लिए उनके कौशल को बढ़ाने पर जोर देती है। प्रमुख युक्तियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रस्तुत करना, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को अद्यतन करना, संकाय विकास कार्यक्रमों का आयोजन और अनुसंधान केंद्र स्थापित करना शामिल है।

विपणन कंपनियों को घरेलू एलपीजी में हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू रसोई गैस की बिक्री पर हुए घाटे के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) को 30,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की है। तेल विपणन कंपनियों को इस क्षतिपूर्ति राशि का वितरण पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यह राशि बारह किस्तों में दी जाएगी।

उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों अर्थात आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल द्वारा विनियमित कीमतों पर आपूर्ति किए जाते हैं।

एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 2024-25 के दौरान उच्च स्तर पर बनी रहीं और आगे भी ऊंची बनी रहेंगी। हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से राहत देने के लिए, बढ़ी हुई लागत का बोझ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया जिससे तीनों तेल विपणन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। घाटे के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है।

इस मुआवजे से तेल विपणन कंपनियों को कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद, ऋण की अदायगी और अपने पूंजीगत व्यय को बनाए रखने जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी जिससे देश भर में एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं की रक्षा करने और साथ ही इन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। यह पहल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत आने वाले घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं को स्वच्छ रसोई ईंधन की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

कैबिनेट ने 2157 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर तमिलनाडु में 4-लेन मरक्कनम-पुडुचेरी राजमार्ग (एनएच-332ए) के निर्माण को मंजूरी दी

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तमिलनाडु में मरक्कनम- पुडुचेरी (46 किलोमीटर) 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का विकास हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) के तहत किया जाएगा, जिसकी कुल पूंजीगत लागत 2,157 करोड़ रुपये होगी।

वर्तमान में, चेन्नई, पुडुचेरी, विलुप्पुरम और नागपट्टिनम के बीच संपर्क मौजूदा 2-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 332ए (एनएच-332ए) और संबंधित राज्य राजमार्गों पर निर्भर है, जहां यातायात की अधिकता के कारण, विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों और गलियारे वाले प्रमुख कस्बों में, काफी भीड़भाड़ रहती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, यह परियोजना मरक्कनम से पुडुचेरी तक लगभग 46 किलोमीटर लंबे एनएच-332ए को 4-लेन में अपग्रेड करेगी। इससे मौजूदा गलियारे पर भीड़भाड़ कम होगी, सुरक्षा में सुधार होगा और चेन्नई, पुडुचेरी, विलुप्पुरम और नागपट्टिनम जैसे तेजी से बढ़ते शहरों की आवागमन संबंधी जरूरतें पूरी होंगी।

यह परियोजना दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच-32, एनएच-332) और दो राज्य राजमार्गों (एसएच-136, एसएच-203) को जोड़ती है, जिससे तमिलनाडु के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक केंद्रों तक निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त, उन्नत गलियारा दो रेलवे स्टेशनों (पुडुचेरी, चिन्नाबाबूसमुद्रम), दो हवाई अड्डों (चेन्नई, पुडुचेरी) और एक छोटे बंदरगाह (कुड्डालोर) से जुड़कर मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन को बढ़ाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में माल ढुलाई और यात्रियों की शीघ्र आवाजाही संभव होगी।

परियोजना के पूरा होने पर, मरक्कनम-पुडुचेरी खंड क्षेत्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, प्रमुख धार्मिक और आर्थिक केंद्रों के बीच संपर्क को मजबूत करेगा, पुडुचेरी में पर्यटन को बढ़ावा देगा और व्यापार एवं औद्योगिक विकास के नए रास्ते खोलेगा। यह परियोजना लगभग 8 लाख मानव-दिवस प्रत्यक्ष और 10 लाख मानव-दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेगी, और आसपास के क्षेत्रों में विकास, प्रगति और समृद्धि के नए रास्ते खोलेगी।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

राजकोट मंडल में डबल ट्रैक कार्य के चलते कुछ और ट्रेनें होंगी प्रभावित

पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल में स्थित लाखाबावल-पीपली-कानालुस सेक्शन में डबल ट्रैक कार्य के चलते 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त, 2025 तक कुछ ट्रेनें प्रभावित होगी। प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

आंशिक रूप से रद्द की गयी ट्रेनें:

1. 21.08.2025 को मुंबई सेंट्रल से रवाना होने वाली ट्रेन नं 22945 मुंबई सेंट्रल-ओखा सौराष्ट्र मेल को जामनगर में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन जामनगर-ओखा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

2. 20.08.2025 को एरणाकुलम से रवाना होने वाली ट्रेन नं 16338 एरणाकुलम-ओखा एक्सप्रेस को हापा में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन हापा-ओखा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

3. 22.08.2025 की ट्रेन नं 22946 ओखा-मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल ओखा की जगह जामनगर से शुरू होगी। इस तरह यह ट्रेन ओखा-जामनगर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

4. 23.08.2025 की ट्रेन नं 16337 ओखा-एरणाकुलम एक्सप्रेस ओखा की जगह हापा से शुरू होगी। इस तरह यह ट्रेन ओखा-हापा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

रिशेड्यूल की गयी ट्रेनें:

1. ट्रेन नं 15635 ओखा-गुवाहाटी एक्सप्रेस 22.08.2025 को ओखा से अपने निर्धारित समय 12.15 बजे की जगह 5 घंटा और 45 मिनट की देरी से 18.00 बजे प्रस्थान करेगी।

2. ट्रेन नं 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 22.08.2025 को पोरबंदर से अपने निर्धारित समय 19.40 बजे की जगह 1 घंटा और 10 मिनट की देरी से 20.50 बजे प्रस्थान करेगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि वे उपरोक्त फेरबदल को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें और ट्रेनों के परिचालन संबंधित नवीनतम अपडेटस की जानकारी के लिए www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन करें ताकि किसी प्रकार कि असुविधा ना हो।

अमित शाह एवं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री,बिहार द्वारा सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ

अमित शाह,गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार एवं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिनांक 08.08.2025 को सीतामढ़ी से नई दिल्ली के लिए एक नई अमृत भारत ट्रेन सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया । आज इसका परिचालन सीतामढ़ी से 05599 सीतामढ़ी-दिल्ली उद्घाटन स्पेशल के रूप में किया गया ।

दिल्ली और सीतामढ़ी के मध्य गाड़ी सं. 14048/14047 दिल्ली-सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन दिल्ली से 09.08.2025 से प्रत्येक शनिवार को तथा सीतामढ़ी से 10.08.2025 से प्रत्येक रविवार को किया जाएगा ।

गाड़ी सं. 14048 दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस 09.08.2025 से प्रत्येक शनिवार को दिल्ली से 14.00 बजे खुलकर गाजियाबाद, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, सिसिवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, सिकटा, रक्सौल, बैरगनिया स्टेशनों पर रूकते हुए अगले दिन 10.45 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी । वापसी में गाड़ी सं. 14047 सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 10.08.2025 से प्रत्येक रविवार को सीतामढ़ी से 22.15 बजे खुलकर उपरोक्त स्टेशनों पर रूकते हुए अगले दिन 22.40 बजे दिल्ली पहुंचेगी ।

विदित हो भारतीय रेल की ओर से बिहार को मिलने वाली यह सातवीं अमृत भारत ट्रेन है। इससे पहले जब देश में पहली बार अमृत भारत ट्रेनें बनकर तैयार हुई थी, तो उनका परिचालन दरभंगा से वाया अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल तथा मालदा टाउन से सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरू के बीच किया गया था। सहरसा और मुंबई के मध्य अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था । इसके अलावा पटना और नई दिल्ली के बीच प्रतिदिन अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ-साथ मोतिहारी से आनंद विहार के लिए, दरभंगा से लखनऊ तथा भागलपुर, गया, सासाराम के रास्ते मालदा टाउन से लखनऊ के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है जिससे बिहार के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है।

अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में किया गया है।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने स्वच्छता अभियान के दौरान किया श्रमदान, पश्चिम रेलवे पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है 'स्वच्छता अभियान'

(पहली तस्वीर) पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर श्रमदान करते हुए। (दूसरी तस्वीर) श्री गुप्ता मुंबई सेंट्रल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह के साथ वृक्षारोपण अभियान में भाग लेते हुए।

पश्चिम रेलवे द्वारा श्रमदान और वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा

मुंबई,

भारतीय रेल द्वारा हमारे देश में मनाये जा रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वच्छता के राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए "स्वच्छता अभियान" मनाया जा रहा है। यह अभियान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी जोनों और उत्पादन इकाइयों में दो चरणों में अर्थात 1 से 15 अगस्त, 2025 तक और उसके बाद 16 अगस्त से 31 अक्टूबर, 2025 तक मनाया जा रहा है। यह अभियान रेलवे के सभी क्षेत्रों अर्थात स्टेशनों, ट्रेनों, कॉलोनियों, कार्यालयों, डिपो और कारखानों आदि में स्वच्छता के प्रति हमारे प्रयासों को दर्शाता है, साथ ही कर्मचारियों और यात्रियों के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देता है।

इसी भावना के साथ पश्चिम रेलवे भी अपने सभी मंडलों और इकाइयों में "स्वच्छता अभियान" का सक्रिय रूप से पालन कर रही है। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने 8 अगस्त, 2025 को मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर श्रमदान में अग्रणी भूमिका निभाई और एक मिसाल कायम की। इस अवसर पर मुंबई सेंट्रल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह और अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारी एवं कर्मचारी भी उनके साथ शामिल हुए। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने अपने संबोधन में स्वच्छता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी को रेलवे स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद श्री गुप्ता ने वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "स्वच्छता अभियान" "स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत" के दृष्टिकोण के अनुरूप सफाई, स्वच्छता, पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी और सामुदायिक सहभागिता पर जोर देता है। इस अभियान की शुरूआत महाप्रबंधक, प्रमुख विभागाध्यक्षों और क्षेत्रीय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों, मंडल स्तर पर मंडल रेल प्रबंधकों और कारखाने स्तर पर मुख्य कारखाना प्रबंधकों द्वारा स्वच्छता शपथ दिलाकर की गई, जिसमें स्वच्छता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। श्री विनीत ने आगे बताया कि कर्मचारियों और जन-स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी से कई स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, स्वच्छ रथ रैलियाँ और प्रभात फेरियाँ आयोजित की जा रही हैं। आम जनता को जोड़ने के लिए स्वच्छता थीम पर आधारित सेल्फी बूथ स्थापित किए गए हैं। कर्मचारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों की भागीदारी से स्टेशनों, कार्यालयों और रेलवे कॉलोनियों में सघन स्वच्छता अभियान और श्रमदान आयोजित किए जा रहे हैं। स्वच्छता कार्यकताओं के लिए स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाए जा रहे हैं। लोगों को स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वच्छता हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं। कैटरिंग कर्मचारियों के लिए जागरूकता अभियान और भोजनालयों, पेंट्री कारों और बेस किचन का निरीक्षण भी किया जा रहा है। यात्रियों को प्लास्टिक कचरे को कम करने और कचरे का उचित निपटान केवल कूड़ेदानों में करने के लिए प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हरित पहल के तहत, विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं।

स्वतंत्रता दिवस समारोह सप्ताह के दौरान स्वच्छता अभियान में पश्चिम रेलवे की सक्रिय भागीदारी स्वच्छता, स्थिरता और सार्वजनिक सहभागिता के प्रति इसकी निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

बजाज समूह के शिशिर बजाज को मिला वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित 'सर्वोत्तम नागरिक सम्मान'

मुंबई, 8 अगस्त। मुंबई के प्रतिष्ठित होटल सहारा स्टार में आयोजित एक भव्य समारोह में बजाज फाउंडेशन के चेयरमैन और बजाज समूह के वरिष्ठ मार्गदर्शक शिशिर बजाज को ह्यसर्वोत्तम नागरिक सम्मान -2025ह्न से सम्मानित किया गया।

महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस सम्मान समारोह में महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति श्रीराम शिंदे तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार द्वारा अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ सम्मान मूर्तियों का सत्कार किया गया।सर्वोत्तम नागरिक सम्मान, मेघा श्रेय फाउंडेशन और श्रीमती सीमा सिंह द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने समाज में अपने निःस्वार्थ समर्पण और सेवा के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में मिसाल कायम की है। इस वर्ष के समारोह में पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर, पद्मभूषण डॉ. विजय भटकर, पद्मश्री डॉ. शंकर महादेवन, फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली, पद्मभूषण अनुपम खेर और पद्मश्री विजेंदर सिंह जैसे कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व उपस्थित रहे। सम्मान प्राप्त करने के बाद श्री शिशिर बजाज ने कहा कि हमारे मूलभूत सामाजिक प्रयास 1926 से शुरू हुए, जब मेरे दादाजी श्री जमनालाल बजाज ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन देने के लिए बजाज समूह की स्थापना की। उन्होंने बताया कि 1932 में उत्तर प्रदेश में हमारी पहली शुगर फैक्ट्री स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य भारत को चीनी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। तब से समूह ने व्यवसाय और सीएसआर दोनों क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण और भारतीय गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आज हम राजस्थान में मेरी जन्म स्थली सीकर जिले के 1000 गाँवों में और मेरे दादाजी की कर्मभूमि महाराष्ट्र के वर्धा जिले के 1000 से अधिक गाँवों में समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य ग्रामीण भारत के प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का बहुमुखी विकास करना है, क्योंकि यह लक्ष्य ह्यविकसित और आत्मनिर्भर भारतह्न के उस निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, जिसकी परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक के लिए निर्धारित की है।

देश के प्रमुख औद्योगिक समूहों में से एक बजाज समूह के परोपकारी संस्थान "बजाज फाउंडेशन" के चेयरमैन शिशिर बजाज वर्ष 2025 का "सर्वोत्तम नागरिक सम्मान" पुरस्कार ग्रहण करते हुए और मंच पर प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ दिखाई दे रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि बजाज फाउंडेशन, श्री शिशिर बजाज और उनके पुत्रों कुशाग्र बजाज एवं अपूर्व बजाज के नेतृत्व में ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। फाउंडेशन ने वर्धा, सीकर और ललितपुर जिलों के गाँवों में वर्षा जल संचयन, नदी पुनर्जीवन, सूक्ष्म सिंचाई, प्राकृतिक खेती, बागवानी, किसान पाठशालाएँ, महिला स्व-सहायता समूह, सौर पंप और बायोगैस संयंत्र जैसे नवीकरणीय ऊर्जा समाधान, किसान उत्पादक संगठन, और परिवर्तनकारी शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 6 लाख से अधिक परिवारों को सशक्त किया है, जिससे लगभग 22 लाख लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। 'नेशन बिल्डिंग थ्रू बिजनेस एंड सर्विस' की विचारधारा के तहत, बजाज समूह भारत के सबसे सम्मानित और विविधीकृत औद्योगिक समूहों में से एक के रूप में स्थापित हुआ है। कुशाग्र बजाज के नेतृत्व में समूह की प्रमुख कम्पनियों में शामिल है, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड जो भारत की सबसे बड़ी एकीकृत चीनी कम्पनी है और उत्तर प्रदेश में 14 चीनी मिलों और 6 एथेनॉल संयंत्रों का संचालन करती है। एक अन्य कम्पनी बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश में 6 पावर प्लांटों का संचालन करती है, जिनमें 1,980 मेगावाट क्षमता वाला ललितपुर पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड का सुपर-क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन भी शामिल है, जो राज्य की लगभग 10% बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड अपने प्रमुख उत्पाद बजाज आमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल के साथ प्रीमियम हेयर ऑयल कैटेगरी में अग्रणी है। समाज सेवा और औद्योगिक उत्कृष्टता के अद्वितीय संगम के रूप में श्री शिशिर बजाज को मिला सर्वोत्तम नागरिक सम्मान पुरस्कार, उनके अभूतपूर्व योगदान की सच्ची पहचान है।

पश्चिम रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस एवं भगत की कोठी के बीच एक अतिरिक्त रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन

मुंबई,

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा त्योहारी सीजन रक्षाबंधन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस एवं भगत की कोठी स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर एक और स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 04828/04827 बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी स्पेशल [2 फेरे]

ट्रेन संख्या 04828 बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी स्पेशल सोमवार, 11 अगस्त, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 10:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04:30 बजे भगत की कोठी पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04827 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल रविवार, 10 अगस्त, 2025 को भगत की कोठी से 14:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, साबरमती, महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, जवाई बांध, फालना, रानी, मारवाड़, पाली मारवाड़ और लूनी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास और द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे।

ट्रेन संख्या 04828 की बुकिंग 09 अगस्त, 2025 से पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

हर्बल दवाओं की सुरक्षा, विनियमन और प्रभावकारिता पर डब्ल्यूएचओ-आईआरसीएच कार्यशाला गाजियाबाद में संपन्न

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी फामाकोपिया आयोग (पीसीआईएमएंडएच) के समर्थन से 6 से 8 अगस्त, 2025 के दौरान गाजियाबाद में तीन-दिवसीय डब्ल्यूएचओ-हर्बल दवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग (आईआरसीएच) कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यशाला का उद्घाटन आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और विश्व स्वास्थ्य संगठन-आईआरसीएच की अध्यक्ष डॉ. किम सुंगचोल ने आयुष मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पीसीआईएमएंडएच के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। भूटान, ब्रुनेई, क्यूबा, घाना, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, पैराग्वे, पोलैंड, श्रीलंका और युगांडा के प्रतिनिधिमंडलों ने जहां इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, वहीं ब्राजील, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

अपने उद्घाटन भाषण में, वैद्य राजेश कोटेचा ने सुरक्षा एवं विनियमन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन-आईआरसीएच कार्य समूह 1 और प्रभावकारिता एवं इच्छित उपयोग पर कार्य समूह 3 के लिए अग्रणी देश के रूप में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने हर्बल औषधि के क्षेत्र में वैश्विक नियामक सहयोग बढ़ाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने आयुष ग्रिड के अंतर्गत प्रमुख डिजिटल पहलों का भी उल्लेख किया, जिनमें भ्रामक विज्ञापनों और फामाकोविजिलेंस की रीयल-टाइम ट्रैकिंग से संबंधित आयुष सुरक्षा पोर्टल और एएसयूएंडएच औषधियों के लाइसेंस से संबंधित एक एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म ई-औषधि शामिल है।

तकनीकी सत्र : इस कार्यशाला में हर्बल औषधियों की सुरक्षा, विनियमन, प्रभावकारिता और इच्छित उपयोग पर विभिन्न देशों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। विशेषज्ञ व्याख्यानों में हर्बल औषधियों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, नियामक केस स्टडीज, पूर्व-नैदानिक अनुसंधान में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली, हर्बल औषधि अनुसंधान में विशिष्ट परिदृश्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2025-2034, नैदानिक परीक्षणों का पंजीकरण, नैदानिक परीक्षणों में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली, और विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा आयुष दोनों दृष्टिकोणों से फामाकोविजिलेंस पर चर्चा की गई। इन सत्रों में हर्बल औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक बेंचमार्क टूल और अश्वगंधा (विथानिया सोम्नीफेरा) की सुरक्षा से जुड़े केस स्टडीज पर भी चर्चा हुई।

व्यावहारिक प्रशिक्षण और अनुभव हासिल करने से संबंधित दौरे

पीसीआईएमएंडएच में व्यावहारिक प्रयोगशाला प्रशिक्षण ने प्रतिभागियों को हर्बल औषधि के मानकीकरण से संबंधित तकनीकों से परिचित कराया, जिसमें औषधीय पहचान और भारी/विषाक्त धातु विश्लेषण शामिल थे। गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, हर्बल उद्यानों, ग्रीनहाउस, पॉलीहाउस, कच्ची औषधि भंडारों, पीसीआईएमएंडएच स्थित संग्रहालयों और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का भ्रमण कराया गया, जिससे भारत की एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालियों की जानकारी मिली।

ह्हर घर तिरंगाह्न अभियान 2025 के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन

"हर घर तिरंगा" अभियान 2025 के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में दिनांक 08.08.2025 (शुक्रवार) को भावनगर मंडल पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एक "तिरंगा प्रदर्शनी" का आयोजन किया गया था। भावनगर डिविजन के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इस प्रदर्शनी का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा जी के कर कमल से एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। भावनगर मंडल के सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया एवं प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय और महिला समिति संचालित किड्स हट तथा बाल मंदिर के बच्चों एवं अध्यापकों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

'हर घर तिरंगा' के इस अभियान के अंतर्गत भावनगर मंडल के मंडल कार्यालय के सभागृह में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भावनगर परा के बच्चे एवं मंडल कार्यालय के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विविध ग्रुप को इस अवसर पर क्वीज कंपटीशन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमांक वाले ग्रुप को प्रोत्साहित किया गया। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन जी की अध्यक्षता एवं उनके मार्गदर्शन में कार्मिक विभाग द्वारा आयोजित किया गया।

पश्चिम रेलवे पर रविवार, 10 अगस्त, 2025 को दिवसकालीन ब्लॉक नहीं

पश्चिम रेलवे के सांताक्रूज एवं माहिम स्टेशनों के बीच 09/10 अगस्त, 2025 की मध्यरात्रि को रात्रिकालीन ब्लॉक

मुंबई,

पश्चिम रेलवे पर रेलपथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु शनिवार/रविवार की मध्यरात्रि अर्थात 09/10 अगस्त, 2025 को सांताक्रूज एवं माहिम स्टेशनों के बीच अप फास्ट लाइन पर 00.00 बजे से 04.00 बजे तक तथा डाउन फास्ट लाइन पर 00.30 बजे से 04.30 बजे तक जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान फास्ट लाइन की सभी ट्रेनें अंधेरी और चर्चगेट स्टेशनों के बीच धीमी लाइन पर चलाई जाएंगी।

तदनुसार, पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड पर रविवार, 10 अगस्त, 2025 को कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।

पश्चिम रेल्वे

अग्रभाग प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान

वरिष्ठ DEE/P/BCT, मुंबई सेंट्रल, मुंबई, निविदा सूचना संख्या: EL-81-919-WA-37, दिनांक : 05.08.2025 आमंत्रित करता है। कार्य एवं स्थान: मुंबई मंडल. चर्चगेट, मुंबई सेंट्रल और वलसाड स्टेशन पर अग्रभाग प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान. कार्य की अनुमानित लागत: ₹5,08,77,205.75/- बयाना राशि: ₹4,04,400/-. जमा करने की तिथि एवं समय: दिनांक : 08.09.2025 के 15:00 बजे तक. खुलने की तिथि एवं समय: दिनांक : 08.09.2025 को 15:30 बजे. अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in देखें। 0472

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद मंडल

निविदा आमंत्रण संख्या - DRM-SnT-ADI- Tele06 वर्ष 25-26

विभिन्न प्रकार के MUX कार्डों का वार्षिक मरम्मत अनुबंध

भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यरत DRM/S और T, निविदा संख्या DRM-SnT-ADI-Tele06 OF 25-26 के अंतर्गत ई-निविदाएँ आमंत्रित करते हैं। अंतिम तिथि 04.09.2025, 15:00 है। बोलीदाता अपनी मूल/संशोधित बोलियाँ केवल अंतिम तिथि और समय तक ही प्रस्तुत कर सकेंगे। इस निविदा के लिए मैन्युअल प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएँगे और प्राप्त किसी भी मैन्युअल प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया जाएगा।

कार्य का नाम:	ADI प्रभाग में विभिन्न प्रकार के MUX कार्डों (वेबफ़िल/पुनकॉम) और STM-1/STM-4 (तेजस) कार्डों का 3 वर्ष के लिए वार्षिक मरम्मत अनुबंध।
कार्य की अनुमानित लागत:	रु. 4996988.00/- (उनचास लाख छियानवे हज़ार नौ सौ अट्ठासी रुपये मात्र)
बयाना राशि:	रु. 99900.00/- (निन्यानवे हज़ार नौ सौ मात्र)
बंद होने की तिथि और समय:	04.09.2025 को 15:00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि और समय:	04.09.2025 को 15:30 बजे
ई-टेंडरिंग की वेबसाइट:	www.ireps.gov.in ADI 129

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

सशक्त डिजिटल कृषि इकोसिस्टम के सृजन के उद्देश्य से डीएएम के तहत एकत्रित डेटा का उपयोग

(जीएनएस)।

सरकार ने सितंबर 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन में देश में एक सशक्त डिजिटल कृषि इकोसिस्टम के सृजन के उद्देश्य से कृषि हेतु एक डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) जैसे एग्री स्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक मृदा उर्वरता एवं प्रोफाइल मैप, और केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई अन्य आईटी पहलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इससे, किसान-केंद्रित नवीन डिजिटल समाधानों को बढ़ावा मिलेगा और सभी किसानों को समय पर विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी उपलब्ध होगी। एग्री स्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से जुड़ी तीन आधारभूत रजिस्ट्रियां या डेटाबेस शामिल हैं, यानी भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र, बोई गई फसल रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री, जिनका निर्माण और रख-रखाव राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।

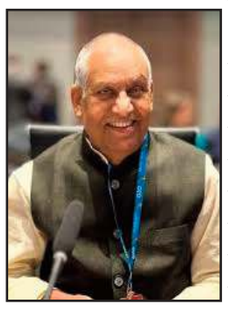

राज्य किसान रजिस्ट्री में सभी भूमि धारक किसान शामिल हैं। 04 अगस्त 2025 तक, कुल 7,04,49,809 किसान आईडी तैयार की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, रबी 2024-25 में 492 जिलों में 23.5 करोड़ से अधिक भूखंडों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया गया है।

एग्री स्टैक किसानों के जनसांख्यिकीय विवरण, भू-जोत और बोई गई फसलों पर व्यापक तथा उपयोगी डेटा प्रदान करता है, जिससे किसान को ऋण, बीमा, खरीद आदि जैसे लाभों और सेवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल रूप से पहचान और प्रमाणीकरण करने में मदद मिलती है। यह राज्यों को किसान-केंद्रित समाधान विकसित करने में भी सक्षम बनाता है जो किसानों को विश्वसनीय एवं पारदर्शी तरीके से इनपुट्स और उपज की ऑनलाइन खरीद व बिक्री सहित डिजिटल अर्थव्यवस्था तक पहुंच प्रदान करता है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर, महाराष्ट्र में खरीफ 2025 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत किसानों के नामांकन के लिए किसान आईडी का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत नामांकन के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी किसान आईडी का उपयोग किया जा रहा है।

भारत में दवाओं के मूल्य औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 ('डीपीसीओ, 2013') के प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाती हैं

(जीएनएस)।

भारत में दवाओं की कीमतें ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 ("डीपीसीओ, 2013") के प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाती हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) डीपीसीओ, 2013 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतें तय करता है। इसके अलावा, डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतें पिछले वित्त वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक (सभी वस्तुओं) के आधार पर हर साल 1 अप्रैल को या उससे पहले संशोधित की जाती हैं। अनुसूचित दवाओं के सभी निमार्ताओं, आयातकों और विपणक को अपने उत्पादों को अधिकतम मूल्य और लागू स्थानीय करों के भीतर बेचना आवश्यक है। एनपीपीए नई दवाओं की खुदरा कीमतें भी तय करता है। इसके अलावा, डीपीसीओ, 2013 असाधारण परिस्थितियों में जनहित में दवाओं के मूल्य निर्धारण और गैर-अनुसूचित दवाओं की मूल्य वृद्धि की निगरानी का भी प्रावधान करता है। तदनुसार, दवाओं, विशेष रूप से कैंसर, मधुमेह और हृदय संबंधी रोगों की दवाओं के मूल्यों को निम्नलिखित तरीके से विनियमित किया जाता है:

एनपीपीए ने 930 अनुसूचित दवाओं के लिए अधिकतम मूल्य तय कर दिए हैं, जिनमें 131 कैंसर रोधी, 11 मधुमेह रोधी और 66 हृदय संबंधी दवाएं शामिल हैं। अनुसूचित दवाओं के सभी निमार्ताओं, आयातकों और विपणकों को अपने उत्पाद अधिकतम मूल्य और लागू स्थानीय करों के भीतर बेचने होंगे। एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत कीमतों के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के कारण औसत मूल्य में लगभग 17% की कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग ₹3,788 करोड़ की अनुमानित वार्षिक बचत हुई।

14.7.2025 तक 3,482 ऐसी नई दवाओं के खुदरा मूल्य भी निर्धारित हैं जिनमें से 1,924 मधुमेह-रोधी, कैंसर-रोधी और हृदय-संबंधी श्रेणियों में हैं। आवेदक निमार्ताओं और विपणन कंपनियों को इन दवाओं को खुदरा मूल्य के भीतर बेचना आवश्यक है।

इसके अलावा, 22 मधुमेह और 84 हृदय संबंधी गैर-अनुसूचित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को सीमित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 350 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होने का अनुमान है।

42 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन पर सीमा लगा दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 526 ब्रांड की दवाओं की कीमतों में औसतन लगभग 50% की कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप मरीजों को लगभग 984 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होने का अनुमान है।

श्री मनोहर लाल खट्टर और डॉ. जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा मिशन पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई

(जीएनएस)।

नई दिल्ली स्थित संसद भवन में आज विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा मिशन पर चर्चा के लिए संयुक्त रूप से एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत के स्वच्छ ऊर्जा बास्केट का विस्तार करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य और नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने को लेकर देश की प्रतिबद्धता को देखते हुए बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान विभिन्न चालू और आगामी परियोजनाओं से 14 गीगावॉट की वृद्धि के माध्यम से भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावॉट से 2032 तक 22 गीगावॉट तक बढ़ाने के रोडमैप की विस्तार से समीक्षा की गई।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलने की सरकार की ऐतिहासिक पहल पर प्रकाश डाला और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) कार्यक्रम के प्रति उद्योगों की ओर से मिली मजबूत और जीवंत प्रतिक्रिया का भी उल्लेख किया। इसके परिणामस्वरूप व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई। अप्रैल में आयोजित चौथी सलाहकार समिति की बैठक के परिणामों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए तेजी से काम किया गया।

विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रगति में तेजी लाने के लिए कई प्रमुख सुझावों की रूपरेखा तैयार की। इनमें नियामक मंजूरी को सुव्यवस्थित करना, प्रलेखन (दस्तावेजीकरण) को मानकीकृत करना, प्रसंस्करण समय सीमा को अनुकूलित करना, सामान्य प्रस्तावों पर जोर देना, लाइसेंसों को समन्वित करना और तकनीकी उन्नयन और क्षमता निर्माण में निवेश करना शामिल हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने निजी क्षेत्र के प्लेयर्स के बीच जागरूकता पैदा करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इनमें से कइयों ने निजी भागीदारी के लिए परमाणु क्षेत्र को खोले जाने पर प्रसन्नता जाहिर की।

ऑनलाइन फार्मेसियों द्वारा नशे की लत वाली दर्द निवारक/मनोरोगी दवाओं की बिक्री

(जीएनएस)।

दर्द निवारक और मानसिक स्वास्थ्य की औषधियों सहित दवाओ की बिक्री और वितरण का विनियमन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (एसएलए) द्वारा किया जाता है। ये अधिनियम और नियमों के अंतर्गत एसएलए को इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन और निगरानी हेतु अधिकार प्राप्त हैं और अनुपालन न होने की स्थिति में, वे उक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।

इसके अलावा, दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को व्यापक रूप से विनियमित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 28.8.2018 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं, जिसमें ई-फार्मेसी के माध्यम से दवाओं की बिक्री और वितरण के विनियमन से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन पर जनता और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

मसौदा नियमों में ई-फार्मेसी के पंजीकरण, समय समय पर ई-फार्मेसी के निरीक्षण, ई-फार्मेसी के माध्यम से दवाओं के वितरण या बिक्री की प्रक्रिया, ई-फार्मेसी के माध्यम से दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध, शिकायत निवारण तंत्र, ई-फार्मेसी की निगरानी आदि के प्रावधान शामिल हैं।

यह जानकारी आज केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

सरकारी ई- मार्केट प्लेस ने 9वां स्थापना दिवस मनाया; वित्त वर्ष 2024-25 में 5.4 लाख करोड़ रुपए का सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया

नए जीईएम सुधारों के तहत 97% ऑर्डर लेन देन शुल्क से मुक्त जीईएम महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, एमएसई, एसएचजी और कारीगरों को मुख्यधारा की खरीद से जोड़ता है

(जीएनएस)।

सरकारी ई- मार्केटप्ले (जेम) ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री के "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के दृष्टिकोण के अनुरूप पारदर्शी, समावेशी और कुशल सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए 2016 में शुरू किया गया यह प्लेटफॉर्म अब एक डिजिटल खरीद प्रणाली के रूप में विकसित हो गया है जो देश भर के विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को जोड़ता है, जिनमें महिला उद्यमी, स्टार्टअप, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई), कारीगर, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और दिव्यांगजन शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024- 25 में, इसने सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) में ₹5.4 लाख करोड़ मूल्य के लेनदेन दर्ज किए।

स वर्ष के स्थापना दिवस समारोह का विषय था "सुगमता, पहुँच और समावेशन"। घोषित प्रमुख सुधारों में विक्रेताओं के लिए सावधानी राशि की समाप्ति, विक्रेता मूल्यांकन शुल्क को युक्ति संगत बनाना और लेन देन शुल्क में कमी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप 97 प्रतिशत ऑर्डरों पर छूट प्राप्त हुई है। इन उपायों का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद को अधिक सुलभ और न्याय संगत बनाना है।

जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मिहिर कुमार ने कहा, "ये सुधार जेम को और भी अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के हमारे इरादे को दर्शाते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि जनजातीय कारीगरों से लेकर तकनीक- संचालित स्टार्टअप तक, हर उद्यम सार्वजनिक खरीद के अवसरों तक आसानी से पहुँच सके।"

इस अवसर पर, 6 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित जेम कार्यालय में एक जेम विक्रेता संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागी शामिल हुए। अधिक समावेशी और भविष्य- तैयार खरीद प्रणाली के निर्माण के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक संवाद कार्यक्रम जेम मंथन भी आयोजित किया गया। यह प्लेटफॉर्म कागज रहित, वास्तविक समय के लेन- देन का समर्थन करता है और स्वास्थ्य, खनन एवं बीमा जैसे क्षेत्रों में अनुबंधों को सुगम बनाता है, नीति कार्यन्वयन को विभिन्न स्तरों पर हितधारकों की भागीदारी से जोड़ता है।

जेम सार्वजनिक खरीद तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए एआई संचालित उपकरणों और एक बहुभाषी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) का उपयोग करता है। ध्वनि- सक्षम नेविगेशन और क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल जैसी सुविधाएँ, दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों सहित, विक्रेताओं के लिए ऑनबोर्डिंग और लेनदेन में सहायता करती हैं।

पिछले नौ वर्षों में, जैम ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। जिनमें वित्त वर्ष 2024-25 में सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) में ₹5.4 लाख करोड़ की वृद्धि, स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), कारीगरों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के साथ-साथ 1.5 लाख महिला- नेतृत्व वाले उद्यमों को शामिल करना। इस प्लेटफॉर्म ने तेज और अधिक लागत- प्रभावी लेनदेन के लिए प्रौद्योगिकी- संचालित खरीद प्रक्रियाओं को लागू किया है, बीमा, जनशक्ति और खान विकास एवं संचालन (एमडीओ) जैसे नए सेवा क्षेत्रों में विस्तार किया है और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण और ऑनबोर्डिंग सहायता प्रदान की है।

छोटे और सीमांत किसानों की वास्तविक आय में वृद्धि

(जीएनएस)।

देश में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय का अनुमान समय-समय पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित 'कृषि परिवारों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (एसएएस)' के माध्यम से लगाया जाता है। सर्वेक्षण के नवीनतम एनएसएस 77वें दौर (जनवरी, 2019-दिसंबर, 2019) के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018-जून, 2019 के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये प्रति माह अनुमानित है।

सरकार ने समय-समय पर विभिन्न नीतियों, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं को क्रियान्वित किया है। इनमें कृषि के सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है, ताकि उत्पादन में वृद्धि, लाभ और आय सहायता प्रदान करके देश में छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की आय में वृद्धि और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए निम्नलिखित एकीकृत रणनीति की पहचान की है :

(i) फसल उत्पादन/ उत्पादकता में वृद्धि

(ii) उत्पादन लागत कम करना

(iii) किसानों की उपज के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके।

(iv) कृषि विविधीकरण

(v) फसल के बाद मूल्य संवर्धन का विकास करना

(vi) जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होना और दीर्घकालिक कृषि के लिए फसल हानि को कम करना।

भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई), उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना, कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) का गठन और 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन (एनबीएचएम) स्टार्ट अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर) कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना राष्ट्रीय कृषि बाजार (आईएसएएमईएनएएम) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) आदि शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़ाकर 2025-26 के दौरान 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है।

खरीफ 2025-26 के लिए बुवाई कार्य अभी भी जारी

(जीएनएस)।

खरीफ 2025-26 के लिए बुवाई कार्य अभी भी चल रहा है। ऐसे में 2025-26 कृषि वर्ष (जुलाई-जून) में सभी प्रमुख खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान अभी तक जारी नहीं किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीफ फसलों के तहत बोए गए कुल क्षेत्रफल में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत वृद्धि/कमी तथा फसल-वार फसल उत्पादन में प्रतिशत लाभ/हानि का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

सरकार कम/अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र के किसानों को सहायता प्रदान करने और उनकी संभावित फसल हानि को कम करने के लिए कई कदम/उपाय उठाती है, जिनमें शामिल हैं:

सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) चला रही है। इसे 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य एक सरल और किफायती फसल बीमा उत्पाद

उपलब्ध कराना है, ताकि बुवाई से पहले से कटाई के बाद तक सभी गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ किसानों को फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित किया जा सके और पर्याप्त दावा राशि प्रदान की जा सके। यह योजना मांग आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है।

इसके अलावा आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें सूखा सहित अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर प्रभावित लोगों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन भी शामिल होता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है न कि मुआवजे के लिए है।

चालू वर्ष के दौरान सूखे के लिए एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता मांगने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई ज्ञापन नहीं भेजा गया है।

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना है। एनएफएसएनएम के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण तकनीक, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन, नई जारी की गई किस्म/हाईब्रिड के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीक, फसल के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण आदि पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

केंद्र सरकार टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से निगरानी और हस्तक्षेप कर रहा है

(जीएनएस)।

चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान खाद्य वस्तुओं की कीमतें काफी हद तक स्थिर और नियंत्रित रही हैं। आज तक, केंद्र सरकार के उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता कार्य विभाग की ओर से निगरानी की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं की कीमतें साल-दर-साल आधार पर या तो स्थिर या घटती प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। जुलाई 2025 में घर पर बनी थाली की कीमत में 14 प्रतिशत की कमी इस महीने खाद्य मुद्रास्फीति में निरंतर कमी को दर्शाती है।

देश भर के विभिन्न केंद्रों पर टमाटर की खुदरा कीमतें किसी बुनियादी मांग-आपूर्ति असंतुलन या उत्पादन में कमी के बजाय अस्थायी स्थानीय कारकों से प्रभावित हैं।

इस संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) 4 अगस्त 2025 से आजादपुर मंडी से टमाटर खरीदकर उपभोक्ताओं को न्यूनतम मार्जिन पर बेच रहा है। एनसीसीएफ ने पिछले वर्षों में भी इसी तरह की पहल की थी।

अब तक, एनसीसीएफ ने खरीद लागत के आधार पर 47 रुपये से 60 रुपये प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्यों पर 27,307 किलोग्राम टमाटर बेचे हैं। टमाटर की खुदरा बिक्री एनसीसीएफ के नेहरू प्लेस, उद्योग भवन, पटेल चौक और राजीव चौक स्थित स्टेशनरी आउटलेट्स के साथ-साथ शहर भर में विभिन्न स्थानों पर संचालित 6-7 मोबाइल वैन के माध्यम से की जा रही है।

दिल्ली में टमाटर का वर्तमान औसत खुदरा मूल्य 73 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस महंगाई की वहज मुख्य रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह से देश के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में हुई भारी बारिश है। इस मौसम संबंधी व्यवधान के कारण जुलाई के अंत तक कीमतें 85 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गईं। हालांकि, पिछले सप्ताह आजादपुर मंडी में दैनिक आवक में सुधार और स्थिरता के साथ, मंडी और खुदरा कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है।

इसके विपरीत, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में, जहां हाल के हफ़्तों में असामान्य मौसम की स्थिति नहीं देखी गई है, कीमतों में ऐसी कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। चेन्नई और मुंबई में टमाटर की वर्तमान औसत खुदरा कीमतें क्रमशः 50 रुपये प्रति किलोग्राम और 58 रुपये प्रति किलोग्राम हैं जो दिल्ली में टमाटर की मौजूदा कीमत से काफी कम है। अभी टमाटर की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 52 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो पिछले वर्ष के 54 रुपये प्रति किलोग्राम और 2023 के 136 रुपये प्रति किलोग्राम से अब भी कम है।

गौरतलब है कि पिछले वर्षों के विपरीत, इस मानसून सीजन में आलू, प्याज और टमाटर जैसी प्रमुख सब्जियों की कीमतें नियंत्रण में हैं।

किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन

(जीएनएस)।

'10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन' के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) पंजीकृत किए गए हैं।

इस योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक एफपीओ को 3 वर्षों में प्रबंधन लागत के रूप में 18 लाख रुपये, प्रति एफपीओ 15 लाख रुपये तक का इक्विटी अनुदान (प्रति किसान 2000 रुपये) और पात्र ऋणदाता संस्थानों से परियोजना ऋण के लिए 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी सुविधा प्रदान की जाती है।

सरकार, राज्यों के साथ समन्वय में इन एफपीओ को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मंडी आदि सहित इनपुट लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे कृषि-व्यवसाय उद्यमों के रूप में कार्य कर सकें। डिजिटल माकेर्टों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एफपीओ को ई-एनएएम (इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट), ओएनडीसी (डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क) और जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है। इस योजना में सभी हितधारकों को डिजिटल मोड के माध्यम से प्रशिक्षण देने का प्रावधान है, ताकि वे अपने कौशल को बढ़ा सकें।

फलों और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) का व्यावसायीकरण

(जीएनएस)।

केंद्र सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत द्विपक्षीय साझेदारों सहित विभिन्न हितधारकों के सहयोग से फलों और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है।

बागवानी में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना क्षमता निर्माण, उत्पादन और संभावित किसानों को रोपण सामग्री की आपूर्ति को बढ़ावा देने और बागवानी क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने के माध्यम से बागवानी उत्पादन में नवीनतम तकनीकों के प्रदर्शन, प्रशिक्षण और प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई है। उत्कृष्टता केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य किसानों, उद्यमियों और विस्तार कार्यकर्ताओं को ज्ञान और व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है, जिससे बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थिरता में वृद्धि हो सके। आधुनिक नवाचारों का प्रदर्शन करके और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करके उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) अनुसंधान और क्षेत्र-स्तरीय अभिग्रहण के बीच की खाई को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पहल उत्कृष्टता केन्द्रों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, नवाचार और प्रौद्योगिकी अनुकूलन को प्रोत्साहित करती है, साथ ही कृषक समाज को आर्थिक लाभ भी प्रदान करती है।